

## पुलसि महानदिशकों का अखलि भारतीय सम्मेलन

### प्रलिमिस के लिये:

पुलसि महानदिशकों का 58वाँ अखलि भारतीय सम्मेलन, पुलसि महानदिशक (DGP), पुलसि महानरीक्षक (IGP), आपराधिकि कानून

### मेन्स के लिये:

महानदिशकों का अखलि भारतीय सम्मेलन

**स्रोत: पी.आई.बी.**

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जयपुर, राजस्थान में पुलसि महानदिशक/महानरीक्षकों के 58वें अखलि भारतीय सम्मेलन में भाग लिया।

- यह तीन दिवसीय कार्यक्रम था जसे हाइब्रिड मोड में पुलसि महानदिशक (DGP), पुलसि महानरीक्षक (IGP) तथा केंद्रीय पुलसि संगठनों के प्रमुखों के साथ आयोजित किया गया था।
- आयोजित सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलसि व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी चुनौतियाँ, वामपंथी उग्रवाद तथा जेल सुधार एवं आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
- सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए [आपराधिकि कानूनों](#) के कार्यान्वयन के लिये रोड मैप पर विचार-विमर्श है।

### प्रधानमंत्री के संबोधन से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं?

- **आपराधिकि न्याय में आदरश बदलाव:**
  - प्रधानमंत्री ने नए आपराधिकि कानूनों के अधनियमन द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन पर प्रकाश डाला तथा नागरकि गरमा, अधिकारों एवं न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाली न्याय प्रणाली को प्राथमिकता देते हुए दंडात्मक उपायों के स्थान पर डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
  - उन्होंने नए कानूनों के तहत महलियों तथा लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के महत्व पर प्रकाश डाला और पुलसि से उनकी सुरक्षा एवं कभी भी, कहीं भी निर्दिश होकर कार्य करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
- **पुलसि की सकारात्मक छवि:**
  - उन्होंने सकारात्मक जानकारी तथा संदेशों के प्रसार के लिये ज़मीनी स्तर पर सोशल मीडिया के उपयोग का सुझाव देते हुए नागरकों के बीच पुलसि के प्रतिसकारात्मक धारणा को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
  - इसके अतिरिक्त आपदा चेतावनी तथा राहत प्रयासों के लिये सोशल मीडिया का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।
- **नागरकि-पुलसि संबंध:**
  - उन्होंने नागरकों तथा पुलसि बल के बीच संबंधों को सशक्त करने के लिये खेल आयोजनों के आयोजन का समर्थन किया।
  - उन्होंने सरकारी अधिकारियों को स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिये सीमावर्ती ग्रामों में रहने के लिये भी प्रोत्साहित किया।
- **पुलसि बल में परिवर्तन:**
  - भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय पुलसि से वर्ष 2047 तकदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एक अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय बल के रूप में विकसित होने के लिये प्रोत्साहित किया।

### पुलसि बलों से सम्बंधित मुद्दे क्या हैं?

- **हरिसत में होने वाली मृत्यु:**
  - हरिसत/अभरिक्षा में होने वाली मृत्यु का आशय पुलसि अथवा अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों की हरिसत में हुई कसी व्यक्तिकी मृत्यु से है।
    - [राष्ट्रीय अपराध रकिंरड बयुरो \(National Crime Records Bureau- NCRB\)](#) के अनुसार नरितर तीन वर्षों

में हरिसत में होने वाली मृत्यु की संख्या वर्ष 2017-18 में 146 से घटकर वर्ष 2020-21 में 100 हो गई जबकि वर्ष 2021-22 में इसकी संख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई तथा यह 175 हो गई।

■ बल का अत्यधिक प्रयोग:

- पुलसि द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की घटनाएँ सामने आई हैं, जिससे चोटें आई और मौतें हुईं।
- उचित प्रशिक्षण और नारीकरण का अभाव कुछ मामलों में बल के दुरुपयोग में योगदान देता है।
  - एक पुलसि अधिकारी एक लोक सेवक है और इसलिये उससे अपने नागरिकों के साथ वैध तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है।

■ भ्रष्टाचार:

- रशिवतखोरी और अन्य प्रकार के कदाचार सहित पुलसि बल के भीतर भ्रष्टाचार, जनता के वशिवास को कमज़ोर करता है।
- उच्च-रैंकिंग के पुलसि अधिकारियों को कभी-कभी भ्रष्ट आचरण में लपित होने के रूप में उजागर किया गया है और नचिली-रैंकिंग के पुलसि अधिकारियों को रशिवत लेने के रूप में भी उजागर किया गया है।
- उदाहरणार्थ: निधि कानून प्रवरत्तन
  - ये कानून शाराब जैसे प्रत्यंबिधति पदारथों की मांग को बढ़ाकर पुलसि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।
  - बढ़ी हुई लाभप्रदता और कानून प्रवरत्तन विकास का संयोजन अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के लिये प्रेरित करता है।

■ वशिवास के मुद्दे:

- पुलसि और समुदाय के बीच वशिवास की बहुत कमी है, जिससे सहयोग तथा सूचना साझाकरण प्रभावित हो रहा है।
- पुलसि कदाचार के हाई-परोफाइल मामले जनता में संदेह और अवशिवास को बढ़ावा देते हैं।

■ पुलसि द्वारा न्यायेतर हत्या:

- आत्मरक्षा के नाम पर पुलसि द्वारा न्यायेतर हत्याओं के कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें आमतौर पर 'मुठभेड़' के रूप में जाना जाता है।
- भारतीय कानून में ऐसा कोई रहस्यमय/अज्ञेय प्रावधान या कानून नहीं है जो मुठभेड़ में की गई हत्या को वैध बनाता हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न नियमों में नीतिगत ज्यादतायों/अतिरिक्त के उपयोग को सीमित कर दिया था।
  - वर्ष 2020-2021 के दौरान एनकार्डर के नाम पर 82 लोगों की हत्या की गई जो वर्ष 2021-2022 के दौरान बढ़कर 151 हो गई।

## पुलसि सुधार के लिये क्या सफिरशिं हैं?

■ पुलसि शक्तियां प्राप्तिकरण:

- [प्रकाश सहि बनाम भारत संघ, 2006 मामले](#) में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने भारत के सभी राज्यों में पुलसि शक्तियां प्राप्तिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया।
  - पुलसि शक्तियां प्राप्तिकरण पुलसि अधीक्षक से उच्च, नीचले स्तर के पुलसि द्वारा कसी भी प्रकार के कदाचार से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिये अधिकृत हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने पुलसिगि/पुलसि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये जाँच एवं कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करने राज्य सुरक्षा आयोग ([State Security Commission- SSC](#)) की स्थापना करने का भी निर्देश दिया, जिसमें नागरिक समाज के सदस्य होंगे और एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

■ राष्ट्रीय पुलसि आयोग की सफिरशिं:

- भारत में राष्ट्रीय पुलसि आयोग (वर्ष 1977-1981) ने कार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए पुलसि सुधारों के लिये सफिरशिं की।

■ श्री रविरो समति:

- पुलसि सुधारों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और आयोग की सफिरशिं को लागू करने के तरीके सुझाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वर्ष 1998 में श्री रविरो समति का गठन किया गया था।
- रविरो समति ने कुछ संशोधनों के साथ राष्ट्रीय पुलसि आयोग (वर्ष 1978-82) की प्रमुख सफिरशिं का समर्थन किया।

■ आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर मलमिथ समति:

- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर वर्ष 2000 में वी.एस. की अध्यक्षता [मलमिथ समति](#) की स्थापना की गई। मलमिथ ने एक केंद्रीय कानून प्रवरत्तन एजेंसी की स्थापना सहित 158 सफिरशिं की।

■ मॉडल पुलसि अधिनियम:

- [मॉडल पुलसि अधिनियम, 2006](#) के अनुसार, प्रत्येक राज्य को सेवानवित्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नागरिक समाज के सदस्यों, सेवानवित्त पुलसि अधिकारियों एवं दूसरे राज्य के सारवजनिक प्रशासकों से बना एक प्राप्तिकरण स्थापित करना होगा।
  - इसने पुलसि एजेंसी की कार्यात्मक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया, व्यावसायिकता को प्रोत्साहित किया और प्रदर्शन एवं आचरण दोनों के लिये जवाबदेही को सर्वोपरिबिनाया।

